

श्रीलंका के विदेश मंत्री मंत्री भारत यात्रा पर, निवेश और मछुआरों के मुद्दों पर होगी बात

नई दिल्ली। भारत की तरफ से श्रीलंका को 50 करोड़ डॉलर की ऋण सहायता देने की घोषणा करने के बाद श्रीलंका के विदेश मंत्री जी एस पीरिस तीन दिन की अधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचे सोमवार को उनको अपने भारतीय समवाय एस. जयवारर ने मुलाकात की। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसुन्धान, विदेश मंत्रालय विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। भारतीय विदेश मंत्री एस जयवारर ने टीवी कर कहा कि मुद्दे श्रीलंका के विदेश मंत्री का स्वाक्षर करते हुए खुशी हो रही है।

गोरखपाल के विदेश मंत्री पीरिस की भारत यात्रा ऐसे समय हो रही है जब कुछ ही दिन पहले भारत ने गहरे विदेशी और ऊर्जा संकट से जूझ रहे पड़ोसी देश श्रीलंका को ईंधन खरीद के वित्तीयों के लिए 50 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा देने की घोषणा की थी।

समझा जाता है कि इस यात्रा के दौरान दोनों पक्ष आपार और निवेश सहित विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। मछुआरों के मुद्दे पर भी



बातचीत होने की संभावना है।

श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में भारतीय उच्चायोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, पड़ोसी देश को पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए 50 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा देने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत के विदेश मंत्री जयवारर ने गत 15 जनवरी को राजपथ के साथ हुई

ऑनलाइन बैठक में श्रीलंका को ऋण सहायता देने पर सम्झौता जारी थी। विदेशी संकट का सामना कर रहे श्रीलंका को तेल की खरीद के लिए फैसला गते जूरूत को देखते हुए भारत ने यह सुविधा देने की घोषणा की थी।

पीरिस की यात्रा के दौरान ऐसी संभावना है कि भारतीय मछुआरों ने 25

में रह रहे तमिल लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने की आवश्यकता पर भी बातचीत करें।

इस बीच श्रीलंका के उत्तरी जाफना प्रायद्वीप की एक अदालत ने जिन 56 भारतीय मछुआरों की रिहा करने का पिछले महीने आदेश दिया था, उन्हें कोविड-19 संबंधी पृथक्वास अवधि समाप्त होने के बाद संपादन के बाहर यहाँ एक अदालत विद्यासंकेत में स्थानांतरित किया जाएगा। कागाम प्राधिकरियों ने यह जानकारी दी।

कागाम अधीक्षक एवं प्रकाश चंदना एकनामकों ने रेखांवर को 'पीटीआई-भाषा' से कहा कि भारतीय मछुआरों ने 25 जनवरी को अपनी रिहाई के बाद उत्तरी प्रान्त के इयाकाच्ची में जेल द्वारा संचालित कोविड-19 पृथक्वास केंद्र में पृथक्वास की अवधि पूरी कर ली है।

एकनामकों ने कहा, "उनमें से कुछ मछुआरे संक्रमित पाए गए थे और अब उनके पृथक्वास की अवधि पूरी हो गई है।

उन्होंने कहा कि उन्हें सोमवार को कोलंबो

सीरिया में कैद हैं सैकड़ों बच्चों के सपने, संयुक्त राष्ट्र भी निराश

दमिश्क। दक्षिण-पश्चिम ईशाई देश सीरिया में बीते 11 वर्षों से लड़ाई का स्वर्गीय खालियाजा बच्चे भगत हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सभा ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जेलों का दौरा कर पाया कि वहाँ जेलों में सैकड़ों बच्चों के सपने कैद हैं। तामाम प्रयासों के बाद भी इन बच्चों को आजादी न मिलने से संयुक्त राष्ट्र भी निराश है।

सीरिया में पिछले 11 वर्ष से जारी भीषण लड़ाई और असाधा ने वहाँ के बच्चों का ना सिर्फ बचपन हाल के दिया है बल्कि अधिकारी की धृतियाँ उड़ा दी हैं। बड़े प्रमाण पर लड़कों और लड़कियों की हत्याएं हुई हैं और उन्हें बलाकर और यौन शोषण की भी शिकाया होता है। इसके अलावा सैकड़ों बच्चे सीरिया की जेलों में कैद होकर अपने सपनों से समृद्धी करने को विचार है। दुनिया में बच्चों के अधिकारी की चिंता करने वाली संयुक्त राष्ट्र सभा की एजेंसी यूनिसेफ के प्रतिनिधियों ने सीरिया की जेलों का दौरा कर वहाँ उनकी दृश्यों स्थिति को लेकर चिंता की है।

सीरिया में यूनिसेफ के प्रतिनिधि विक्टर नाइलंड ने कहा कि जेलों में बंद बच्चों की स्थिति अविश्वसनीय रूप से बहुत खराब है। नाइलंड ने कहा कि यूनिसेफ इन बच्चों के साथ हो रहे हैं अत्याचार का दीर्घकालिक समाधान खोजने पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें सोमवार को कोलंबो में एक अदालत विद्यासंकेत के लिए उस देश

जाएगा।

कोविड-19: काठमांडू में पांबदियां की जाएंगी कम, स्कूल दोबारा खुलेंगे



बायान में कहा गया कि अगले

सप्ताह से स्कूल और कोलंबो में कम्बिए अनुमति दी जाएगी। पिछले महीने से बंद सिनेमाघर, जिम और अन्य सर्वजनिक स्थलों को भी सामान्य रूप से खोलने और संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

काठमांडू जिला प्रशासन ने एक

बायान में कहा कि वह सोमवार से

स्कूल यात्रायात पर यात्रा पार्टी हड्डी देता

है। जिसके तहत वाहनों को एक दिन छोड़कर एक दिन सम्बिधय आधार पर चलने की अनुमति दी जाएगी।

काठमांडू जिला प्रशासन के लिए

अनुमति दी जाएगी।

काठमांडू जिला प्रशासन ने एक

बायान में कहा कि वह सोमवार से

स्कूल यात्रायात पर यात्रा पार्टी हड्डी देता

है। जिसके तहत वाहनों को एक दिन

छोड़कर एक दिन सम्बिधय आधार पर चलने की अनुमति दी जाएगी।

काठमांडू जिला प्रशासन के लिए

अनुमति दी जाएगी।

काठमांडू जिला प्रशासन ने एक

बायान में कहा कि वह सोमवार से

स्कूल यात्रायात पर यात्रा पार्टी हड्डी देता

है। जिसके तहत वाहनों को एक दिन

छोड़कर एक दिन सम्बिधय आधार पर चलने की अनुमति दी जाएगी।

काठमांडू जिला प्रशासन के लिए

अनुमति दी जाएग

सम्पादकीय

कैंसर की चुनौती से ज़ुझता भारत

प्रतिवर्ष चार फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर सौ से अधिक प्रकार हैं, लेकिन इनमें स्तन, सर्वांगिकल, ब्रेन, हड्डी, एंटरल, पैंक्रियाटिक, प्रोस्टेट, गर्भाशय, किढ़ी, फेफड़ा, त्वचा, पेट, यथरॉयड और मुंह व गले का कैंसर प्रमुख हैं। वजन बढ़ने, शरीरिक क्रियता में कमी आने, दोषपूर्ण व असंतुलित खान-पान, व्यायाम नहीं रखने, अल्कोहल के अधिक मात्रा में सेवन से इस रोग के होने की भावना अधिक रहती है। चाय-कॉफ़े जैसे पेय पदार्थों के आदि व्यक्ति भी कैंसर का ज्यादा खतरा रहता है। मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति को कैंसर होने की अधिक संभावना होती है। यह बीमारी अनुर्वांशिक भी है। शेषज्ञों का मानना है कि लोगों की बदलती जीवनशैली, तनाव, खान-पान की आदतें, शराब और तंबाकू सेवन इसकी बड़ी वजह बन रही हैं। ऐसा में पापांत्रा, मंस-सर्वांगिकल थैरेपी सर्वत्र कैंसर के पापांत्रा में केंद्री

दश म सामान्य, मुहुर, सवाइकल आर स्टन कंसर के मामले म तजा वृद्धि हुई है। नेशनल हेल्थ प्रोफ़इल-2019 की रिपोर्ट के मुताबिक, एनसीडी क्लीनिक ने 2017 से 2018 के बीच कैंसर के मामलों की ज्ञान की है। इस एक वर्ष में देश में कैंसर के मामले तीन गुना से भी बढ़ा बढ़ गये। वर्ष 2017 में राजस्थान के सरकारी एनसीडी केंट्रों में चंचे करीब 30 लाख (30,91,378) लोगों में से 1,358 लोगों को मान्य कैंसर निकला। वर्ही 2018 के दौरान यह आंकड़ा बढ़कर 3,414 गया। यह करीब डेंगुना बढ़तेरी है। वर्ष 2017 में 3,57,23,660 ग जांच कराने पहुंचे, जिनमें से 39,635 लोगों में सामान्य कैंसर पाया गया। वर्ष 2018 में 6,51,94,599 लोग जांच कराने पहुंचे, जिनमें से 68,122 में सामान्य कैंसर की पुष्टि हुई। गुजरात में 2017 में 3,939 सर पर्फिडिटों की पुष्टि हुई थी। वर्ष 2018 में यह संख्या बढ़कर 72,169 गयी। गुजरात के बाद सबसे खराब हाल कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल का रहा। हर दिन औसतन 1300 से अधिक लोग इस मारी का शिकार हो रहे हैं। हर वर्ष कैंसर के 10 लाख नये मामलों का दान किया जा रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार, 2020 तक कैंसर के मामलों में 25 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है और 2035 तक हर वर्ष कैंसर के कारण मरनेवालों की संख्या बारह लाख बढ़ने की उमीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत में कैंसर से प्रभावितों ने दर कम है। बावजूद यहाँ 15 प्रतिशत लोग कैंसर के शिकार होकर अपनी जान गंवा देते हैं। डल्क्यूएचओ की सूची के अनुसार, 172 देशों ने सूची में भारत का स्थान 155वां हैं। वर्तमान में कुल 24 लाख लोग ने भारतीय का शिकार हैं। एक अनुमान के मुताबिक, भारत में 42 प्रतिशत पुरुष और 18 प्रतिशत महिलाएं तंबाकू के सेवन से कैंसर का शिकार होकर अपनी जान गंवा चुके हैं। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के एक टेक्नोलॉजी टेंप्स में दो वर्ष हमारीपांि में 70 टेक्नोलॉजी की हम आर वे की समझदारी के ईंट-गिर्ड घूमता है, अतीत के साथ जारी यह अंतःक्रिया अक्सर बेहद बुरे किस्म के एकालाप में तब्दील हो जाती है, जहां कुल मिला करने उसका असर वर्तमान में लोगों के मन मस्तिष्क को विश्वास करने के लिए, पूर्वग्रहों से लैस करने के लिए उसके इस्तेमाल किया जाता है, जहां फिर वह न अतीत से सही उसके जरिए भविष्य का गता तालाश सकते हैं। ऐसी तमाम मिसालें आए दिन मिलती हैं, जो बताती हैं कि हिन्दुत्व वर्चस्ववादी के संकीर्ण चिन्तन ने उन्हें हास्यास्पद नतीजों तक पहुंचाया है। अब फिल्मकृत इतिहास के साथ जारी यह अलग किस्म की हिंसा सप्तांशीक महान (ईसा पूर्व 303 से ईसा पूर्व 232 तक) के संदर्भ में उर्ज पर है, जहां हिन्दुत्व दक्षिणपथ की तरफ से उनके नायक नहीं खलनायक के तौर पर पेश किया जा रहा है, एक ऐसे उगल बादशाह के साथ उनकी तुलना की जा रही है-जिसकी अपनी छिक वो पहले ही सुनियोजित तरीके से बिगाड़ा जा चुका है - जो एक तरह से धार्मिक कटूरता और करूरता का प्रतीक बना दिया गया है। अशोक महान, जो मौर्य साम्राज्य के आखरी बड़े शासकों में गिरे जाते हैं, लेकिन इतिहास अशोक को उसके साम्राज्य की व्याप्ति के लिए नहीं याद करता बल्कि इसलिए याद करता है कलिंग युद्ध के बाद-जिस पर अशोक की सेनाओं ने आक्रमण किया था-जो जबरदस्त हिंसा हुई, जिसमें डेंग लाख से अधिक लोग मारे गए। उसके बाद अशोक को इस समूचे हिंसाचार का जबरदस्त पश्चात्पात हुआ और उन्होंने अपना शेष जीवन धर्म के

तवदन के अनुसार, देश म हर वध इस बीमारी से 70 हजार लागा का मृत्यु हो जाती है, इनमें से 80 प्रतिशत लोगों की मौत का कारण बीमारी प्रति उदासीन रवैया है। कैंसर संस्थान की इस रिपोर्ट के अनुसार, रत में हर वर्ष सामने आ रहे साढ़े बारह लाख नये रोगियों में से गंभग सात लाख महिलाएं होती हैं। इनमें से करीब साढ़े तीन लाख हेलाओं की मौत हो जाती है। इनमें से भी 90 प्रतिशत की मृत्यु का कारण रोग के प्रति बरती जाने वाली लापरवाही है। ये महिलाएं डॉक्टर पास तभी जाती हैं जब बीमारी अनियंत्रित हो जाती है। निःसंदेह, यदि ई देश अपने को कैंसर मुक्त बनाने का सपना देखता है, तो उसे अपने यहाँ में विक रहे मादक व नशीले पदार्थों व शराब की फैक्ट्रियों पर रोक लगाने के कदम उठाने होंगे। जंक फूड पर फैट टैक्स लागू कर इसके सेवन आमजन को बचाने का प्रयत्न करना होगा। कैंसर से बचाव के लिए हमें यह रोग को लेकर जन-जागृति कार्यक्रमों में तेजी लाने की जरूरत है।

समावेशी विकास पर हो जोर

सत्ता में आने के साथ वर्तमान सरकार ने समावेशी विकास का भरोसा लाया था, जहां सभी लोगों के लोग विकास प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं और वको समान रूप से पफयदा होता है। ऐसा तब होता है, जब भारत जैसी गरीब वर्ष्यवस्था में आबादी के निचले 40 फीसदी हिस्से की आय में बढ़ि शीर्ष 10 फीसदी लोगों से अधिक हो, लेकिन हालिया प्रकाशित ऑक्सफैम घटना रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2015 से निचली 40 फीसदी आबादी कीमत पर शीर्ष के एक फीसदी लोगों के पास अधिक आय जाती रही है। वर्ष्य एक फीसदी के पास राष्ट्रीय संपत्ति का 42.5 फीसदी है, जबकि निचली 50 फीसदी आबादी के पास महज 2.8 प्रतिशत हिस्सा ही है। देश के बसे धनी 100 अरबपतियों की संपत्ति 775 अरब डॉलर है और उनका न-सहन सबसे गरीब 55.50 करोड़ (आबादी का 40 फीसदी) से बिल्कुल लगा है। साल 2020 में 5.90 करोड़ लोग बेंद गरीब थे, जिनकी संख्या 21 में बढ़ कर 13.40 करोड़ हो गयी, जबकि अरबपतियों की संख्या 40 फीसदी की बढ़ती हुई स्पष्ट है कि आबादी का निचला तीस से लीस फीसदी हिस्सा हाशिये पर है और वर्चित है। उत्तापद रोजगार में बड़ा स्तर समावेशी विकास की मूलभूत शर्तों में है, लेकिन देश में महामारी से लेने ही 45 सालों की सबसे अधिक बेरोजगारी दर थी, जो बीते दो सालों और बढ़ी है। बजट में इस समस्या का कोई समाधान नहीं दिया गया है। तत मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम में नी खर्च बढ़ाने से आगामी पांच सालों में 60 लाख रोजगार सुजित होंगे। इससे बेरोजगारों की बड़ी संख्या कम करने में खास मदद नहीं मिलेगी। इंप्रॉस्ट्रक्चर कास ठीक है, पर इससे सही रोजगार सृजन में समय लगता है। गति शक्ति कार्यक्रम में भागीदारी के लिए अपेक्षित राज्यों के पास संसाधनों और क्षमता कमी है। ग्रामीण लोगों के लिए मनरेगा एक तरह की जीवन रेखा साबित होती है। अपने दोनों राज्यों में 25 फीसदी जीवन रेखा साबित होती है। यह विधानसभा चुनाव ही रह है, पर उनमें 10 मात्र का धारापत्र किए जाएंगे। स्वाभाविक है कि इन पांच राज्यों के मतदाताओं ने इसके प्रभाव को ध्यान में रखा है। उनकी आजीविका पर बजट निश्चित रूप से सकारात्मक नहीं है भारतीय आबादी के कमजौर छोपर लोगों के लिए कुछ भी ठोस नहीं है। बजट को निश्चित रूप से लोकल बुधवार नहीं कहा जा सकता है जो आम तौर पर चुनावी वर्ष में कुछ छूट देने की प्रवृत्ति है। फिर यह कैसे हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बेदाग राजनीतिक प्रवृत्ति से एक ऐसे बजट पेश करने की अनुमति दी, जिसका पांचों चुनावी राज्यों में लाखों गरीबों पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री और उनके सलाहकारों सत्ता में बने रहने के लिए अति आत्मविश्वासी हैं और वे वर्तमान के संकट को नजरअंदाज करते हुए 25 साल के अमृत काल में फैले भविष्य की योजना बना सकते हैं। यह एक भूल के आधार पर एक आत्मशान बहुमंजिलता अपार्टमेंट बनाने जैसा है जिसमें कई छेद हैं। हमारे प्रधानमंत्री शीर्ष मंजिल की ओर इस उम्मीद से देख रहे हैं कि भारत बड़ी लीग में शामिल हो रहा है। प्रधानमंत्री को भविष्यवादी रूप में होने का पूरा अधिकार है, लेकिन वह एक दूरसरी के रूप में कार्य कर सकते हैं, यदि उन्होंने कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखा होता, जिसमें तक्ताल भविष्य में सार्वजनिक खपत को बढ़ावा देने के तरीके शामिल होते हैं ताकि अर्थव्यवस्था को लघु और मध्यम अवधि के आधार पर बढ़ावा दिया जा सके। प्रमुख अर्थशास्त्रियों द्वारा गरीबों

ह. अब मनसा के आवंटन में 25 फैसदी का कटाता कर दा गया है। इस व्यर्कम के तहत 20 हजार करोड़ रुपये की मजदूरी बाकी है। ऐसे में आगामी लों में ग्रामीण रोजगार प्रभावित होगा। शहरों में भी रोजगार गारंटी योजना होने से बेरोजगारी बढ़ी। बजट में खाद्य अनुदान में 28 फैसदी तथा ईलाइजर और पेटोलियम सब्सिडी में 11-11 फैसदी कमी की गयी है। मीण विकास के बजट में 0.3 प्रतिशत की कटौती हुई है, जबकि कृषि बजट में महज 2.5 फैसदी वृद्धि की गयी है। मुद्रासंस्थिति के महेनजर, बदल के बजूद इस मध्यम में कमी हो सकती है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बजट में कुछ खास नहीं दिया गया है। पिछले साल अर्थव्यवस्था में कुल उपभोग खर्च में पांच फैसदी की गिरावट आयी। नगदी हस्तांतरण के अभाव और अपर्याप्त रोजगार के कारण उपभोग बढ़ने की संभावना नहीं है, खासकर राष्ट्रीयति के उच्च स्तर में, जिसका कोई स्पष्ट समाधान सरकार के पास नहीं आगामी सालों में मांग में कमी जारी रह सकती है, जिससे एक ओर निजी विवेश बाधित होगा, तो दूसरी ओर आबादी के निचले हिस्से के लिए शेकेल बढ़ती रहेंगी। स्वास्थ्य में आवंटन में मात्र एक प्रतिशत की वृद्धि की गयी है, जो मुद्रासंस्थिति के हिसाब से ऋणात्मक हो सकता है। शिक्षा का बजट एवं बंटन 11 फैसदी बढ़ा है, जो वास्तविक रूप से कम हो सकता है। आश्र्य एक बात है कि सरकार शिक्षा में दो साल के नुकसान के बाद स्कूली शिक्षा के लिए 200 टीवी चौनल स्थापित करना चाहती है, वह भी तब जब स्कूल बने-धीरे खुलने लगे हैं। यह बहुत देर से उठाया गया कदम है। सरकार ने सारी सेवाएं से स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सृजन, कृषि निवेश और छोटे-मझोले उद्यमों के लिए खर्च बढ़ा सकती थी। साथ ही, नगद हस्तांतरण से गरीबों के उपभोग में वृद्धि कर सकती थी। इन सबसे समावेशी विकास को बड़ी गति लाती। यह सब धनिकों पर कर लगाकर किया जा सकता था। लेकिन बजट कराधान से संवर्धित कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभी संपत्ति कर रखने वाले भी पिछले साल के स्तर पर हैं तथा अन्य करों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। कर राजस्व में बढ़ातेरी अर्थव्यवस्था में अब जल की वजह से है। कर और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात भारत में 5 म है। यह 2017-18 में 10.7 फैसदी था, जो 2020-21 में घटकर 9.9 प्रतिशत हो गया। इस जीडीपी के स्तर पर यह शायद दुनिया में सबसे कम नुपातों में से है। इसे बढ़ाने की बड़ी संभावनाएँ हैं। निष्कर्ष के तौर पर कहा सकता है कि आबादी के निचले 30-40 फैसदी हिस्से के लिए सरकार प्रतिबद्धता बहुत सीमित प्रतीत होती है। सरकार का मुख्य ध्यान विभिन्न कर की उचित-अनुचित सुविधाएं देकर शीर्षस्थ धनिकों और कॉर्पोरेट कर को अधिक धनी बनाने पर लगा दुआ है। सरकार अभी भी सकल लूप उत्पादन की उच्च वृद्धि दर हसिल करने को अपना बड़ा लक्ष्य मानती लेकिन उसे इस विकास की संरचना की परवाह नहीं है।

हिन्दूत्व के पैरोकार अशोक महान से खफा क्यों

सुभाष गाताडे

इतिहास क्या है ? ...वह इतिहासकार और तथ्यों के बीच निरंतर चलनेवाली निरंतर प्रक्रिया है, एक समास न होने वाला संवाद जो वर्तमान और अतीत के बीच जारी रहता है। प्रख्यात ब्रिटिश इतिहासकार ई एच कार (1892-1982), जो मशहूर रहे हैं सोवियत यूनियन के इतिहास पर 14 खंडों में लिखी अपनी किताब ऐ हिस्ट्री आण सोवियत यूनियन के लिए, उन्होंने इतिहास की समझदारी को अपने अंदाज में प्रस्तुत किया था। निस्सन्देह, ऐसे लोगों, समझों के लिए जिनकी समझदारी का प्रस्थान बिंदु



जरिए अर्थात् नैतिक जीवन के सिद्धांतों के आधार पर लोगों को जीतने में इस्तेमाल किया। वह दुनिया के ऐसे शासकों में अग्रणी माने जाते हैं जिन्होंने अस्पतालों के निर्माण, सड़कों के किनारे पेड़ लगाना, कुएं खुदवाना तथा ठहरने के ठिकाने बनाना आदि सार्वजनिक उपयोग के कामों का राज्य की तरफ से शुरू कियाथ जिनकी सार्वजनिक तर्कशीलता के प्रति प्रतिबद्धता जबरदस्त थी आर ईसापूर्व दो सौ साल पहले उन्होंने दुनिया की पहली आम सभाएं बुलायीं, जिन्हें शेष दुनिया भी महान सम्प्रायों की फैफरिस्त में शुमार करती है, वह खलनायक के तौर पर पेश किए जा रहे हैं। इस मामले में रिटायर्ड नौकरशाह दया प्रकाश सिन्हा, जो लेखक तथा नाटककार भी हैं, और जिनकी केसरिया समूह से नजदीकी खुला रहस्य है, उनके विवादास्पद बयान सुर्खियों में हैं। जनाब सिन्हा, जो भाजपा के सांस्कृतिक सेल के राष्ट्रीय कन्वेनर भी हैं और इंडियन कौन्सिल पैर कल्चरल रिलेशन्स (आईसीआर) के उपाध्यक्ष भी हैं तथा जिन्हें अपने नाटक सम्प्राट अशोक के लिए पिछले साल ही साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, और जो इस साल 2021 पदमश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं, उनका सम्प्राट अशोक को लेकर साक्षात्कार बायरल हो चुका है उपरोक्त सक्षात्कार में-जिसे एक राष्ट्रीय अखबार में जगह मिली है-सिन्हा अशोक महान का सिलसिलेवार खंडन करने का प्रयास करते दिखते हैं। अपनी प्रस्तुति में वह सम्प्राट अशोक की तुलना करूरता के मामले में मुगल बादशाह

आरागजब स करत ह। यह साक्षात्कार कालग युद्ध के पहले के अशोक के जीवन पर केंद्रित करता है तथा उनकी जिन्दगी के सही गलत किस्सां को जोड़ कर उन्हें एक ऐसे शासक के तौर पर पेश करता है, जिन्होंने अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न किया, यहां तक कि अपने कई आत्मीयजनों को मार डाला। मुश्किल तब पेश हुई जब सम्राट अशोक के इस प्रकट अपमान को लेकर बिहार की राजनीति में उताल आया और संघ-भाजपा को बचावात्मक पैंतरा अखिलयार करना पड़ा। दरअसल जनता दल (यू) जिसके साथ भाजपा बिहार में सत्ता में साझेदारी कर रही है - उसने साफ किया कि बिहार के पाटलिपुत्र से शासन करने वाले सम्राट अशोक वी यह बदनामी हिन्दुत्ववादी संगठनों की तरफ से ही की जा रही है और फिर बिहार के अन्य कई राजनीतिक दलों ने भी जनता दल यू का इस मामले में साथ दिया। राजद भी खुल कर समर्थन में उत्तरा। मांग उठी कि सिह्ना से न केवल पद्मश्री वापस ली जाए, साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी छीन लिया जाए तथा उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएं। अपना राजनीतिक नफ-नुकसान देखते हुए भाजपा को पहल लेनी पड़ी और बिहार के एक अग्रणी भाजपा नेता ने न केवल सिन्धा के संघ-भाजपा के साथ किसी रिश्ते से इन्कार किया और पुलिस स्टेशन जाकर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। वैसे इस मसले पर फिल्मकष्ट संभव था भाजपा जो भी प्रलाप करे, इस बात के तमाम प्रमाण उपलब्ध हैं कि उनका चिन्तन किस प्रकार का है। हाल के समयों में ऐसे पांच्युलत लेखक भी सामने आए हैं, जिन्होंने भारतीय इतिहास पर किताबें प्रकाशित की हैं, जो हिन्दुत्व वर्चस्ववादी नजरिये के साथ काफी सामंजस्य रखती दिखती हैं। ऐसी ही श्रेणी में शुमार है एक किताब द ओशन आफर्चर्च, हाउ द इंडियन ओशन शेष द्व्यूमन हिस्टरी जिसके लेखक हैं जनाब संजीव सान्ध्याल-जो फिल्मकृ भारत सरकार के वित मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनोमिक अफेयर्स में प्रमुख आर्थिक सलाहकार के तौर पर तैनात हैं। अपनी उपरोक्त किताब में वह भी अशोक के महिमामंडन को प्रश्नांकित करते हैं। यह जनाब भी अशोक के प्रारंभिक कर्तृ और अलोकप्रिय शासन के बारे में बात करते हैं और ऐतिहासिक कलिंग युद्ध के बाद अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के स्वीकार के स्थापित तथ्य का भा प्रश्नाकृत करत ह। किताब म वह यह दावा करते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म का स्वीकार कलिंग प्रसंग के दो साल पहले किया था। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक के पश्चात्ताप का भी मजाक उड़ाते हुए वह यह भी लिखते हैं कि बौद्ध धर्म का स्वीकार दरअसल युद्ध से उपजे पश्चात्ताप के कारण नहीं बल्कि उत्तराधिकार की राजनीति से जुड़ा था। गौरतलब है कि संजीव सान्ध्याल के विवादास्पद दृष्टिकोणों पर इतिहास के गंभीर अध्येताओं की निगाह गई है, जिसमें इस तथ्य को नोट किया गया है कि किस तरह वह ऐतिहासिक अनुसंधान की बुनियादी प्रणालियों के बारे में भी अनभिज्ञ हैं और इतिहास के पुनर्नीखन के बड़े-बड़े दावों के बावजूद वह कभी इतिहास के प्रायमरी स्रोतों पर गौर नहीं करते हैं और अपनी दलीलों को लोकप्रिय इतिहास और अखबारी लेखनों के प्रमाणों के जरिए पुष्ट करते हैं। स्पष्ट है कि केन्द्र में सत्ताधीन हिन्दुत्व वर्चस्ववादी हुक्मत और समाज के मुख्य हिस्से में इस नजरिये की बढ़ती स्वीकार्यता के चलते, सम्राट अशोक जैसे भारत के गौरवशाली इतिहास के एक कर्णधार की बदनामी का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। सम्राट अशोक ने जिस भारत का तसव्वुर किया था, सब निवासियों के मिलजुल कर रहने की, प्रगति करने की बात की थी उससे उनकी गहरी बेआरामी होती है। वे सभी लोग, समूह, संगठन भारत को हिन्दु राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिन्होंने हकीकत में धार्मिक अल्पसंख्यकों को हर जगह बचावात्मक पैंतरा अखिलयार करने के लिए मजबूर किया है और जो इसी हिसाब से सर्विधान को भी तब्दील करना चाहते हैं, क्या उनसे कभी उम्मीद की जा सकती है कि सम्राट अशोक के जीवन के वास्तविक मर्म को समझेंगे निश्चित ही ऐसे संकीर्णमना लोग जिन्होंने आजादी के अंदोलन से दूरी बनाए रखी उन्हें निश्चित ही यह बात हजम नहीं होगी कि न्याय और अहिंसा के अशोक के सिद्धांतों ने आजादी के गांधी-नेहरू जैसे रहनुमाओं को प्रेरित किया था। यह अकारण नहीं कि सम्राट अशोक जो सांस्कृतिक और धार्मिक बहुलतावाद के हामी थे, उनके प्रतीक चार शेरों की तस्वीरें भारतीय मुद्रा पर अंकित हैं और उनका चक्र भारतीय तिरंगे के केन्द्र में है।

मोदी सरकार के नौवें बजट प्रस्तावों से असमानता और बढ़ेगी

नित्या चक्रवर्ती

नरेंद्र मोदी सरकार के बजट 2022-23 को कोइ कैसे दर्शाता है? बजट तब पेश किया गया जब महामारी की तीसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन निश्चित रूप से पूरे देश में इसकी तीव्रता कम हो रही है। महामारी से प्रभावित लोगों का संकट जारी है और अब तक के सभी अध्ययनों ने संकेत दिया है कि भारतीय समाज में असमानता बढ़ गई है क्योंकि गरीबों और मध्यम वर्ग की आय का स्तर काफी नीचे चला गया है। राजनीतिक स्तर पर, देश के पांच राज्यों में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, परिणाम 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। स्वाभाविक है कि इन पांच राज्यों के मतदाताओं ने इसके प्रभाव को ध्यान में रखा है। उनके आजीविका पर बजट निश्चित रूप से सकारात्मक नहीं है भारतीय आबादी के कमजोर छोर पर लोगों के लिए कुछ भी ठोस नहीं है। बजट को निश्चित रूप से लोकलभावक नहीं कहा जा सकता है जो आम तौर पर चुनावी वर्ष में कुछ छूट देने की प्रवृत्ति है। पर यह कैसे हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बेदाम राजनीतिक प्रवृत्ति से एक ऐसे बजट पेश करने की अनुमति दी, जिसका पांचों चुनावी राज्यों में लाखों गरीबों पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री और उनके सलाहकारों सत्ता में बन रहने के लिए अति आत्मविश्वासी हैं और वे वर्तमान के संकट को नजरअंदाज करते हुए 25 साल के अमृत काल में फैले भविष्य की योजना बना सकते हैं यह एक भूतल के आधार पर एक आलीशान बहुमंजिल अपार्टमेंट बनाने जैसा है जिसमें कई छेत्र हैं। हमारे प्रधानमंत्री शीर्ष मंजिल की ओर इस उमीद से देख रहे हैं कि भारत बड़ी लोग में शामिल हो रहा है। प्रधानमंत्री को भविष्यवादी होने का पूरा अधिकार है, लेकिन वह एक दूरदर्शी के रूप में कार्य कर सकते हैं, यदि उन्होंने कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखा होता, जिसमें तकाल भविष्य में सार्वजनिक खपत को बढ़ावा देने के तरीके शामिल होते हैं ताकि अर्थव्यवस्था को लघु और मध्यम अवधि के आधार पर बढ़ावा दिया जा सके। प्रमुख अर्थशास्त्रियों द्वारा गरीबों



सुपर रिच पर एक तरह का असमानता कर लगाने के सुझाव दिए गए थे। इसके बजाय, मनरेगा, ग्रामीण गरीबों के लिए आजीविका की धरी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो कमज़ोर लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है, के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है जैसे कि गरीबों के लिए कार्यक्रमों का विस्तार विकास विरोधी है। इसके बजाय, कॉर्पोरेट करों में कटौती की गई है। 2022-23 के बजट से एक सप्ताह पहले जारी भारत पर ऑक्सफैम असमानता रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से उजागर किया है कि कैसे दो साल की महामारी ने भारत सहित दुनिया में असमानता को चौड़ा किया है। विशेष रूप से भारत के लिए, स्थिति गंभीर है क्योंकि वर्तमान सरकार में गरीबों और संकटग्रस्त लोगों की सुरक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का अभाव है जिसके परिणामस्वरूप गरीबों की आजीविका में और गिरावट आई है। पिछली बजट ने मनरेगा के लिए आवंटन को प्रभावी रूप से घटाकर केवल रुपए 73,000 करोड़ किया है जो संशोधित अनुमान से काफ़ी कम है। लेकिन तथ्य यह है कि हाल के सभी अध्ययनों से पता चला है कि मनरेगा कार्यक्रम ने जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के द्विमार्ग की उपज थी, पिछले दो वर्षों की महामारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में संकटग्रस्त लोगों के लिए बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार को यह पता था लेकिन गरीबों का ख्याल रखना मोदी की सची में प्राथमिकता नहीं है। पीड़ीएस

एक बांध है, को भी रुपये के संशोधित आबंटन से कम आबंटन दिया गया है। 2021-22 में 2,10,929 करोड़ रुपये से 2022-23 में 1,45,920 करोड़ रुपये। बुनियादी ढांचे के लिए निवेश में बड़ी बढ़ोत्तरी निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, लेकिन भारत में बड़े आधे को अपनी आजीविका बनाए रखनी होगी और उनके रहने की स्थिति में सुधार होगा सार्वजनिक खपत में वृद्धि के कारण आर्थिक विकास हुआ। इस प्रकार मोदी सरकार, कमजोर लोगों की आजीविका की न्यूनतम अनिवार्यताओं की परवाह किए बिना वैश्विक आयाम की एक नई अर्थव्यवस्था की आकंक्षा कर रही है। पिछले आठ वर्षों में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने विकास पथ का अनुसरण किया जिसने केवल असमानताओं को चौड़ा किया है और अमेरिंद्रा गरीबों और भारतीय समाज के निचले तबके की कीमत पर लाभ कमाने के लिए हर आर्थिक संकट का पफ्फदा उठाया गया है। पिछले दो वर्षों की महामारी में मोदी सरकार द्वारा संकटप्रस्त लोगों को तथाकथित रियायतों पर लगातार सरकारी घोषणाओं के बावजूद यह प्रक्रिया तेज हो गई है। 24 मार्च, 2020 को अचानक से लॉक डाउन की घोषणा के साथ पहली लहर (6.8 बिलियन डॉलर) कर सकता है। इसके बजाय, भारत में कराधान का बोझ वर्तमान में भारत के मध्यम वर्ग और गरीबों के कंधों पर है, और कोविड-19 वस्तूली के लिए अमीरों पर एकमुश्त कर के प्रस्ताव को संबोधित नहीं करने के परिणामस्वरूप सरकार का उपयोग कर रही है। केवल अन्य उपलब्ध विकल्प यानी अप्रत्यक्ष कर राजस्व के माध्यम से धन जुटाना जो गरीबों को दर्दित करता है, रिपोर्ट में कहा गया है। सितंबर 2019 में, कोविड-19 महामारी से पहले, मोदी सरकार ने घेरू निर्माताओं के लिए कॉर्पोरेट कर की दरों को 30-पीसदी से घटाकर 22 पीसदी कर दिया था, और नई निर्माण कंपनियों के लिए, दर को 25 पीसदी से घटाकर 15 पीसदी कर दिया था, बशेत् वे ऐसा करें किसी प्रकार की छू का दावा न करें। सरकार ने इस निर्णय को लागू करने में 36 घंटे का समय लिया, नियम 12 की मदद से जो प्रधानमंत्री को निर्णय लेने और बाद में कैबिनेट का अनुसमर्थन प्राप्त करने का अधिकार देता है। अमेरिका स्थित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एस एंड पी ग्लोबल ने इस कदम को क्रेडिट नकारात्मक करार दिया था।

से लेकर वर्तमान तीसरी लहर तक, वेतन पाने वाले, एसएमई के कर्मचारी, प्रवासी श्रमिक और निजी क्षेत्र की छोटी कंपनियों के लाखों कर्मचारी घटे में चल रहे हैं। नौकरी छूटने, छंटनी और आय में कमी के साथ घोर गरीबी। ये बे लोग थे, जिन्हें मंदी का भी सामना करना पड़ा। भारत में असमानता पर ऑक्सफैम की वार्षिक रिपोर्ट में मोदी सरकार के शासन ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो कुछ लोगों द्वारा धन के संचय को बढ़ावा देता है, जबकि बाकी आबादी को सुरक्षा जाल प्रदान करने में विफल रहता है। रिपोर्ट में भारत में अमीर और गरीब पर कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव पर भी प्रकाश डाला गया। विभिन्न थिंक टैंकों द्वारा इतने आलोचनात्मक उल्लंघनों के बावजूद नवीनतम बजट में भी वही पुराना दृष्टिकोण जारी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल इन अति-समृद्ध परिवारों पर उनकी संपत्ति का केवल 1 पीसदी कर लगाकर, भारत अपने संपूर्ण

साइबर हर्गी से बचाव के साथ संबंधित संगठनों की तय हो जवाबदेही

डा. महेश परिमल

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पूकृन्यायाधीश पूनम श्रीवास्तव के बैंक खाते से झारखंड के साइबर अपराधियों द्वारा पांच लाख रुपये की ठगी के सभी आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि साइबर ठगी के मामले में पैसे की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक की होनी चाहिए। अदालत ने माना कि बैंक में पैसे जमा करने वाले देश के प्रति ज्यादा ईमानदार हैं हर हाल में उनका पैसा सुरक्षित रहना चाहिए। इससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है कालाबाजारी करने वाले लोग पैसा तहखाने में रखते हैं, जो देश के विकास में काम नहीं आता। कोर्ट ने कहा कि बैंक यह कहकर नहीं बच सकती कि वह इसके जिम्मेदार नहीं है। इसके साथ ही पुलिस भी यह कहकर नहीं बच सकती कि साइबर अपराधी उनकी पहुंच से दूर नक्सली क्षेत्रों में रहते हैं। एक बात तो तय है कि इस एक उदाहरण के अलावा भी ऐसे उदाहरण आपको मिल सकते हैं जिनमें साइबर ठगी पर सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों का रवैया ढिला-ढाला ही रहा है लिहाजा साइबर ठगी की जबाबदेही तय होनी चाहिए। व्यापार-उद्योग तथा दैनंदिन जीवन में डिजिटल ट्रांजेक्शन लगातार बढ़ रहा है। लेकिन उस तेजी से साइबर सिक्योरिटी सिस्टम का उपयोग नहीं बढ़ रहा है। ऐसे में साइबर क्राइम या आनलाइन ठगी की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे साइबर क्राइम के कारण



साइबर सिक्योरिटी एक नई इंडस्ट्री के रूप में उभर रही है। अब देश भर में साइबर सिक्योरिटी का बाजार डेढ़ लाख करोड़ रुपये वार्षिक पार कर गया है। साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत इस पर नियंत्रण का काम शुरू किया। इधर जैसे-जैसे सख्ती बढ़ती गई, अपराधियों ने भी नए-नए पैतरे आजमाने शुरू कर दिए। लेकिन इस दिशा में पुलिस अभी तक पूरी तरह से सजग नहीं हो पाई है। साइबर सेल का अलग विभाग बना देने के बाद भी वहां अपने मोबाइल के खो जाने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए कई बार चक्कर लगवाया जाता है। कुल मिलाकर पुलिस इस दिशा में अभी तक सचेत नहीं हुई है। इसलिए साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। कोर्ट की फटकार के बाद भी पुलिस अपनी जवाबदेही से बचना चाहती है। इस अपराध में सबसे बड़ी बात यह है कि लोग आधुनिक तकनीक की पूरी जानकारी नहीं रखते। थोड़ी-सी ही जानकारी

के आधार पर लोग अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि का प्रयोग असावधानीवश करते रहते हैं। इस अपराध में अपराधी सामने नहीं होता। वह सुदूर क्षेत्रों में या फिर विदेश में बैठकर भी यह अपराध कर लेता है। अधिकारियों की लापरवाही के कारण इन साइबर अपराधियों को मौका मिल जाता है इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों में लालच का भाव भरा हुआ है। मुफ्त में मिलने वाली किसी भी चीज के लिए वे इन्कार नहीं करते। इसलिए वे प्रलोभन का शिकार हो जाते हैं। अपराधी उनकी इसी कमजोरी का पूरा फयदा उठाते हुए उन्हें ठग लेते हैं। सामान्य जनता आधुनिक संसाधनों का खबूल नहीं करती है। या समाज उन्हें देने के बाबा

इस्तमाल करता है, पर सजगता नहीं हान के कारण वह अक्सर ठगी का शिकार हो जाती है। जनता यह नहीं सोचती कि आजकल कोई आपको मुफ्त में एक कप चाय नहीं पिलाता, तो फिर वह क्यां केवल आपको लाखों रुपए यूं ही दे देगा। ये अपराधी मानव के भीतर की लालसा को जगाकर उनसे ठगी कर लेते हैं। बैंक द्वारा बार-बार यह आग्रह किया जाता है कि किसी अनजान को कभी अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर या ओटीपी न दें। बैंक कभी किसी से फेन पर किसी भी तरह की जानकारी नहीं मांगती। फिर भी लोग लालच में आकर ठगी का शिकार हो जाते हैं। व्यापार में पूँजी निर्माण के लिए और अपने व्यापार को बनाए रखने के लिए साइबर सुरक्षा अनिवार्य हो गई है। वैश्विक स्तर पर कारपोरेट बिजेनेस में साइबर ठगी की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक अनुमान

इलियाना डिक्रूज

ने शेयर की नॉन-एडिटेड बोल्ड
तस्वीर, फैंस बोले-‘जो Ileana से
जले जरा साइड से चले’

इलियाना डिक्रूज (Ileana D'Cruz) सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड फोटोज और वीडियो शेयर करती रहती हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस इलियाना की ट्वैमरस तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। अब इलियाना ने रेड कलर के बिकिनी में बिना एडिट किए तस्वीर शेयर की है। साथ ही बताया है कि उन्होंने ऐसे सारे ऐसे डिलीट कर दिए हैं जो उन्हें स्लिम दिखाते हैं। ‘बिग बुल’ (The Big Bull) एक्ट्रेस ने अपनी बॉडी को लेकर कॉन्फिंडेंट रहने का मैसेज भी दिया है।

‘जो इलियाना से जले जरा साइड से चले’

दरअसल, इन दिनों कई ऐप्स आ गए हैं जो आपकी तस्वीर को स्लिम ट्रिप दिखाते हैं। इसका यूज एक्ट्रेस से लेकर तमाम महिलाएं और लड़कियां करती रहती हैं। खुद की तस्वीर में फिट दिखने के लिए ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल इन दिनों धड़ले से किया जा रहा है। ऐसे में इलियाना डिक्रूज ने सीख देते हुए इंस्टाग्राम पर अपनी बिना फिल्टर वाली बिकिनी फोटो शेयर की है। एक्ट्रेस ने बताया भी है कि बिना किसी एडिटिंग ऐप्स के इस्तेमाल की फोटो है। खुद को स्लिम या टोंड दिखाने के लिए किसी तरह के ऐप्स यूज नहीं किया है। इलियाना के इस कर्तम की फैंस तारीफ करते हुए उन्हें गौर्जियस बता रहे हैं। फैंस लगातार तारीफ कर रहे हैं तो वहीं एक ने मजेदार कमेंट करते हुए लिखा कि ‘जो इलियाना से जले जरा साइड से चले’।

इलियाना ने दिया स्ट्रॉन्ग मैसेज

इलियाना डिक्रूज (Ileana D'Cruz) ने इंस्टा स्टोरी पर अपनी बिकिनी फोटो शेयर कर बताया कि सभी फोटो एडिटिंग ऐप्स को फोन से हटा दिया है। एक्ट्रेस ने लिखा ‘ऐसे ऐसे में फैसना आसान है जो आपकी बॉडी को आसानी से चेंज कर

देते हैं, जिससे आप स्लिम, टोंड दिखते हैं.. मुझे गर्व है कि मैंने उन सभी ऐप्स को हटा दिया है। ये मैं हूं और मैं हर इंच, हर कर्व को पसंद करती हूं’।

इलियाना को आते थे सुसाइड के ख्याल

बता दें कि इलियाना डिक्रूज ने पहले भी कहा था कि वह बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर से पीड़ित थीं, जिसकी वजह से उन्हें सुसाइड करने का ख्याल थी आया। इलियाना ने बताया कि किस तरह से ऐसी समस्या छुटकारा पाया। एक्ट्रेस ने थेरेपी की मदद से इससे उबर पाई। एक्ट्रेस ने समझ लिया है कि हमे अपनी बॉडी से प्यार करना चाहिए, हमेशा सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है।

इलियाना डिक्रूज के वर्कफँट की बात करें तो आधिग्री बार उन्हें अभिषेक बच्चन के साथ ‘द बिग बुल’ में देखा गया था। इलियाना रणबीर कपूर के साथ ‘बर्फी’ में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा ‘रुस्तम’, ‘हैप्पी एंडिंग’, ‘फटा पोस्टर निकला हीरो’ जैसी फिल्मों में नजर आई थीं।

अब अनुपमा पर चढ़ा ‘कच्चा बादाम’ का खुमार, लेकिन अनुज को ना देख निराश हो गए फैन

बंगाली लोक गीत ‘कच्चा बादाम (Kacha Badam)’ ने इन दिनों इंटरनेट पर धूम मचाई

हुई है। कुछ हफ्ते पहले जब से यह गाना सोशल मीडिया (Social Media) पर सामने आया है, तब से कई हस्तियां कच्चा बादाम पर रील्स बना कर इंस्टाग्राम और अलग-अलग सोशल मीडिया प्लॉटफॉर्म्स पर चैलेंज के रूप में ऐसे शेयर कर रहे हैं। हाल ही में, अनुपमा (Anupamaa) यानी रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) ने भी इस चैलेंज को स्वीकार किया और अपने भतीजे के साथ वायरल हो रहे बंगाली गाने पर डांस किया।

अनुपमा द्वारा ने अपने शानदार डांस पूज्य से इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। वीडियो में रुपाली गांगुली मस्टर्ड कलर के सूट में नजर आ रही हैं, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लगा रही हैं। रुपाली अपने डांस के साथ ही अपने खूबसूरत लुक से भी फैंस के बीच चर्चा में आ गई हैं। वीडियो पर कमेंट करते हुए कई यूजर उनके खूबसूरत अंदाज की तारीफ कर रहे हैं। वहीं

कुछ यूजर रुपाली गांगुली से उनके अनुपमा के को-स्टार गौरव खना यानी अनुज को लेकर भी सवाल कर रहे हैं।

डांस वीडियो को शेयर करते हुए रुपाली ने लिखा, जब मैं एक ट्रॉडिंग बंगाली गाना सुनती हूं तो मेरे अंदर का बंगाली हावी हो जाता है अपने भतीजे के साथ मस्ती करते हुए। बता दें, रुपाली गांगुली टीवी टाइन की सबसे ज्यादा फैंस पाने वाली एक्ट्रेस बन गई हैं। अनुपमा के जरिए अब घर-घर की पसंद बन चुकी रुपाली गांगुली एक एपिसोड का 3 लाख वसूलती हैं। बॉलीवुड लाइफ के मुताबिक, रुपाली गांगुली कथित तौर पर अनुपमा के लिए प्रति एपिसोड 3 लाख रुपये कमा रही हैं। फूलपाली गांगुली ने प्रति दिन 1.5 लाख रुपये की फीस के साथ शुरूआत की थी। लेकिन, अब वह रोजाना 3 लाख रुपये कमा रही हैं। ह भारतीय टीवी पर सबसे अधिक फीस पाने वाली एक्ट्रेस बन गई हैं। उन्होंने इस इंडस्ट्री से जुड़े अन्य लोकप्रिय युवा सेलेब्स को पीछे छोड़ दिया है।



गोल्ड स्मग्लिंग केस में Bigg Boss में दिख चुकी मशहूर एक्ट्रेस से पूछताछ, नाम और सर्जरी से बदलने का आरोप!



अभिनेत्री अक्षरा रेडी (Akshara Reddy) कमल हासन (Kamal Haasan) द्वारा होस्ट किए गए ‘बिग बॉस 5 टमिल’ की स्टर प्रतियोगियों में से एक थीं, जिसका हाल ही में विजेतीवी पर समाप्त हुआ है। एक्ट्रेस बिग बॉस हाउस से 84वें दिन बाहर निकली थीं और बाद में उन्होंने ग्रैंड फिनाले के दौरान 104वें दिन बातौर गेस्ट पर बाकर पर्टीपाईट किया। इन दिनों एक्ट्रेस का नाम कानूनी विवादों को लेकर सुखियों में है जिसके लिए उनसे हाल ही में कोजिकोड ईडी के दफ्तर (Kozhikode office of ED) में पूछताछ हुई। 2013 में के गोल्ड स्मग्लिंग मामले में शामिल अक्षरा का करीबी केरल मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक, सोने की तस्करी का मामला 2013 में दर्ज किया गया था, जिसके सिलसिले में अक्षरा को प्रत्यन्त निदेशालय (Enforcement Directorate) ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ऐसा कहा जाता है कि केरल में कोजिकोड ईडी कार्यालय में उससे कई घंटों तक पूछताछ की गई थीं और इस मामले को लेकर एक बार फिर एक्ट्रेस चर्चा में है। indiaglitz के अनुसार, अक्षरा पर आरोप लगाया गया है कि असली नाम श्रव्य सुधाकर (Shravya Sudhakar) है और उसे उस बक मॉडलिंग में थी जब सोने की तस्करी के मामले के बाबत आया था। बताया जाता है कि इस सनसनीखेज मामले में अभिनेत्री के एक करीबी को शामिल पाया गया है।

अक्षरा पर है असली पहचान छिपाने के आरोप

बता दें कि गोल्ड स्मग्लिंग मामले (Gold smuggling case) में अक्षरा के जिस दोस्त के शामिल होने की बात हो रही है उसका नाम फैज है जो बड़कारा के मूल निवासी है। 19 सितंबर, 2013 को कोच्चि हवाई अड्डे के माध्यम से बुकरा पहने दो महिलाओं को 20 किलो सोने की तस्करी करते हुए पकड़ा गया था। अक्षरा पर ये भी आरोप है कि गोल्ड स्मग्लिंग केस के बाबत ही उन्होंने न सिफर अपना नाम बदला बल्कि अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई।

मामले में मुख्य आरोपी सहित 2 कस्टम अधिकारी भी हुए थे अरेस्ट

जांच टीम ने बाद में तस्करी के मामले में मुख्य आरोपी फैज और दो कस्टम अधिकारियों (Customs officials) को गिरफ्तार किया था। जांच से पता चला था कि फैज के फिल्मी हस्तियों से संबंध थे। अधिकारियों को पहले ही शक था कि फैज फिल्म इंडस्ट्री में सोने की तस्करी के जरिए कमाए गए पैसे का इस्तेमाल कर रहा है।

पूनम पांडे अब करना चाहती है मां-बहन के रोल, बोली- जब लोग मुझे बोल्ड कहते हैं, तब...



पूनम पांडे (Poonam Pandey) बीते दिनों पति सैम बॉम्बे (Sam Bombay) के साथ हुए अपने विवाह को लेकर सुखियों में रही थीं। पूनम पांडे ने अपने पति के खिलाफ मुंबई पुलिस में मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। एक्ट्रेस की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने सैम बॉम्बे को गिरफ्तार कर लिया था। दूसरी तरफ अपनी बोल्ड और ग्लैमरस इमेज के चलते भी पूनम पांडे विवादों से परिवर्ती हो रही हैं। लेकिन, अब एक्ट्रेस अपनी इस इमेज से बाहर आना चाहती है और कुछ सीरियस रोल करना चाहती है।

पूनम पांडे का कहना है कि वह अब बोल्ड और ग्लैमरस रोल्स से अलग सीरियस किरदार निभाना चाहती है। वह दर्शकों को अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाने के लिए फिल्मों में मां-बहन के रोल करना चाहती है। एक इंटरव्यू में पूनम पांडे ने सीरियस रोल निभाने की अपनी इमेज, सोशल मीडिया पोस्ट्स और फैंस से बदलने के लिए ऐसे बोल्ड वीडियोज और तस्वीरों डालती हूं। मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर करती हूं और मैं ऐसी ही हूं हो सकता हूं कि हमारी सोसाइटी जाहिर की है। इसके लिए उन्होंने अपनी इमेज, सोशल मीडिया पोस्ट्स और पैरों इंडस्ट्री पर भी बदला दिया है। लेकिन जब आप मुझे बोल्ड कहते हैं तो ये मेरे पति एक्ट्रेस बहुत ही खूबसूरत शब्द है।” मैं अब तक जितने लोगों से मिली हूं, वे सब अलग हैं। और उन्हें मुझसे कहती हैं कि मेरे पति आपको बहुत पसंद करते हैं। कपल्स मेरे साथ फोटोज किलक करते हैं। लोग अब अपन माइंड ही चुके हैं और ये सब देखकर अच्छा लगता है। मैं सोशल मीडिया पर जो कुछ करती हूं,

